

5



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]
No. 104]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, जून 26, 2003/आषाढ़ 5, 1925
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 26, 2003/ASADHA 5, 1925

नागर विमानन मंत्रालय

(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जून, 2003

फा. सं. एएआई/पर्स/ई डी पी ए/आर ई जी/2002.— भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 42 की उपधारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या और उपचार) विनियम, 1976 और राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (चिकित्सा परिचर्या) विनियम, 1988 को, उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रान्त करते हुए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कर्मचारी की चिकित्सीय परिचर्या और उपचार) विनियम 2003 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

(3) ये निम्नलिखित के सिवाय प्राधिकरण के सभी कर्मचारियों को लागू होंगे ;

(क) वे व्यक्ति जो, नैमित्तिक या दैनिक दर पर हैं या अंशकालिक नियोजन में हैं ;

(ख) वे व्यक्ति जो प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर हैं जब तक उनकी प्रतिनियुक्ति के निबंधन अन्यथा उपबंध न करते हों ;

(ग) वे व्यक्ति जो संविदा पर नियोजित हैं जब तक उनकी संविदा के निबंधन अन्यथा उपबंधित न करते हों ;

(घ) वृत्तिका पर शिक्षु या प्रशिक्षु।

2. परिभाषाएं- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) “अधिनियम” से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) अभिप्रेत है ;

(ख) “प्राधिकरण” से अधिनियम की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ग) “प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी” से ऐसा चिकित्सा अधिकारी जो प्राधिकरण द्वारा या तो पूर्णकालिक, अंशकालिक या रिटेनर आधार पर नियुक्त किया गया है या ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जिसके पास बैचलर आफ मेडिसिन और बैचलर आफ सर्जरी/बैचलर आफ डेंटल सर्जरी/बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम/ बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम जैसी न्यूनतम अर्हता हो, अभिप्रेत है ;

(घ) “अध्यक्ष” से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन नियुक्त प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ङ) “नगर” से कर्मचारी का मुख्यालय नगर या शहर अभिप्रेत है ;

(च) “सक्षम प्राधिकारी” से अध्यक्ष या पूर्णकालिक सदस्य या इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी अभिप्रेत है ;

(छ) “औषधालय” से इन विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा स्थापित औषधालय अभिप्रेत है ;

(ज) “कर्मचारी” से प्राधिकरण का पूर्णकालिक कर्मचारी अभिप्रेत है ;

(झ) “कुटुंब” से कर्मचारीवृन्द, यथास्थिति पति या पत्नी तथा माता पिता (सौतेला माता पिता नहीं), अपत्य और सौतेले अपत्य, दत्तक ग्रहीत अपत्य (यदि दत्तक ग्रहण स्थानीय विधि द्वारा अनुज्ञेय हो), बहन, विधवा बहन, विधवा पुत्री, अवयस्क भाई, जो आश्रित के लिए अधिकथित शर्तों के अनुसार कर्मचारी पर पूर्णतया आश्रित हैं, अभिप्रेत है ;

(ञ) “अस्पताल” से कोई औषधालय या प्राधिकरण द्वारा स्थापित या चलाया गया चिकित्सा निरीक्षण कक्ष या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय

प्राधिकारी या पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा प्रशासित प्रसूति केंद्र, सेना अस्पताल, रेल अस्पताल, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्थापित या चलाया गया या कोई मान्यताप्राप्त कोई चिकित्सा संस्थान या महाविद्यालय या अनुसंधान केंद्र, या समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित कोई अस्पताल अभिप्रेत है ;

(ट) “चिकित्सा परिचर्या” से किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा, जिसके पास बैचलर आफ मेडिसिन एंड बैचलर आफ सर्जरी/ बैचलर आफ डेंटल सर्जरी/ बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम/ बैचलर आफ यूनानी मेडिसिन सिस्टम जैसी न्यूनतम अर्हता हो, किसी अस्पताल या नर्सिंग होम या क्लीनिक में या कर्मचारी के निवास स्थान पर परिचर्या अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निदान और/ या उपचार के लिए ऐसी कोई जांच भी है जो उक्त चिकित्सा अधिकारी या चिकित्सा व्यवसायी द्वारा आवश्यक समझी जाए ;

(ठ) “सदस्य” से प्राधिकरण के पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य अभिप्रेत है ;

(ड) “नर्सिंग होम” से प्राधिकरण के पैनल पर नर्सिंग होम अभिप्रेत है ;

(ढ) “वेतन” से मूल वेतन, विशेष वेतन या अन्य परिलब्धियां जो उपचार के समय कर्मचारी द्वारा आहरित वेतन के रूप में वर्गीकृत की गई हैं, अभिप्रेत है ;

(ण) “उपचार” से चिकित्सा और / या शल्य चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग जो प्राधिकृत चिकित्सा परिचर द्वारा आवश्यक समझा जाए, अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत निम्नलिखित है:-

- (i) विकृति विज्ञान संबंधी, जीवाणु विज्ञान संबंधी, विकीरण चिकित्सा संबंधी और अन्य पद्धतियों को काम में लाना ;
- (ii) औषधि, टीका, सीरम या अन्य आरोग्य पदार्थों का प्रदाय ;
- (iii) कृत्रिम दांतों, क्राउन वर्क, ब्रिज वर्क, आर्थोडेंटिक वर्क और अन्य विशेषज्ञीय दंत क्रिया के सिवाय सामान्य दंत उपचार ;

- (iv) आंखों का उपचार और दृष्टिशक्ति का परीक्षण चश्मा प्रदाय करने के सिवाय ;
- (v) प्रसवपूर्व प्रसूति प्रतिरोध और प्रसवोपरांत उपचार ;
- (vi) मधुमेह से पीड़ित रोगियों के मामले में संबंधित विशेषज्ञ द्वारा सिफारिश किए जाने पर और जब भी अपेक्षित हो, इन्सुलिन उपचार ;
- (vii) अलर्क रोधी उपचार ;
- (viii) सामान्य परिचर्या तथा कर्मचारी की प्रास्थिति के अनुसार अस्पताल वास स्थान ; और
- (ix) संबंधित विशेषज्ञ के परामर्श पर किया गया विशेष परीक्षण और अन्वेषण ।

(2) उन शब्दों और पदों को जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों में हैं ।

3. निर्भरता के लिए शर्तें :- (1) कुटुम्ब का ऐसा सदस्य, जिसकी सभी स्त्रियों से, जिसके अंतर्गत पेंशन, पेंशन पर अस्थायी वृद्धि या वृत्तिका भी है, कुल आय 1500 रूपए प्रतिमास से अधिक नहीं है, कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित समझा जाएगा । तथापि, पति और पत्नी इन विनियमों के प्रयोजन के लिए एक यूनिट के रूप में समझे जाएंगे तथा निर्भरता संबंधी सीमा पत्नी या पति को लागू नहीं होगी ।

टिप्पण:-

- (i) सक्षम प्राधिकारी आश्रित संबंधित सीमा में या आश्रितता की शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा है या इन विनियमों के अधीन कुटुम्ब (जिसके अन्तर्गत पति या पत्नी हैं, के सदस्यों के लिए कोई अतिरिक्त शर्त हटा सकेगा, जोड़ सकेगा या परिवर्तित कर सकेगा ;
- (ii) प्रत्येक कर्मचारी प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ में अपने माता पिता और कुटुम्ब के अन्य सदस्यों की प्रास्थिति तथा आश्रितता के बारे में एक घोषणा उन्हें इन विनियमों के अधीन चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अनुज्ञात करने हेतु प्रस्तुत करेगा ।

स्पष्टीकरण-

- (i) कुटुंब के सदस्यों के लिए निवास की शर्त अनिवार्य नहीं है। कुटुंब के सदस्य यदि वे कर्मचारी के साथ नहीं रहते हैं, चिकित्सा परिचर्या और उपचार ले सकते हैं। माता पिता कुटुंब के अन्य सदस्यों के साथ कर्मचारी से दूर निवास कर सकते हैं परंतु यह तब जब कर्मचारी ने स्थानांतरण के समय माता पिता और कुटुंब के लिए यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता का दावा नहीं किया है।
- (ii) अन्य स्रोतों से जैसे कारबार, नियोजन, संपत्ति, कृषि, गृह, भूधृति आदि से आवर्ती आय को आय के निर्धारण के प्रयोजन के लिए गणना में लिया जाएगा ;
- (iii) एक मुश्त अनावर्ती आय जैसे अंशदायी भविष्य निधि फायदे, भारत सरकार के मूल्य बंध पत्र, उपदान, संराशित उपदान, बीमा फायदे आदि को आय के भाग रूप नहीं माना जाएगा।
- (2) ऐसे मामलों में जहां पति और पत्नी दोनों प्राधिकरण में नियोजित हैं तो वे तथा उनके पात्र आश्रित उनकी प्रास्थिति के अनुसार, चिकित्सीय रियायतें प्राप्त करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए इस बारे में एक संयुक्त घोषणा प्रस्तुत की जानी होगी कि पति या पत्नी और अपत्यों पर ध्यान दिए बिना चिकित्सा परिचर्या और उपचार पर उपगत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कौन दावा प्रस्तुत करेगा। यदि घोषणा नहीं प्रस्तुत की जाती है तो रियायत पति की प्रास्थिति के अनुसार पत्नी सहित सभी द्वारा उपभोग की जाएगी। घोषणा में किया गया विकल्प परिस्थितियों के परिवर्तन पर निर्भर करते हुए जब भी आवश्यक हो, अगले वित्तीय वर्ष से परिवर्तित किया जा सकता है।
- (3) यथास्थिति केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्थानीय निकायों या प्राइवेट संगठनों में जो चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराते हैं, नियोजित कर्मचारियों के पति या पत्नी को या तो इन विनियमों के अधीन सुविधा चुनने या उस संगठन द्वारा जिसमें वह नियोजित है पति या पत्नी के नियोजक से ऐसे प्रमाण पत्र के आधार पर सुविधा चुनने के लिए अनुज्ञात है कि वह अपने पति या पत्नी की और अपने कुटुंब के सदस्यों की बाबत चिकित्सा सुविधा का दावा नहीं कर रहा है / कर रही है। इस प्रयोजन के लिए, वे अपने प्राधिकारियों को दो प्रतियों में संयुक्त घोषणा प्रस्तुत करेंगे कि वे पत्नी या पति और आश्रित कुटुंब सदस्यों की बाबत उनके

बारे में पूर्ण ब्यौरों सहित चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा करेंगे। दो प्रतियों में संयुक्त घोषणा की एक प्रति उनके संबंधित संगठनों में उनमें से प्रत्येक की वैयक्तिक फाइल में लेखबद्ध की जाएगी। घोषणा में किया गया विकल्प जब भी आवश्यक हो आगामी वित्तीय वर्ष से परिवर्तित किया जा सकता है।

(4) जब कर्मचारी जिसके पति या पत्नी अन्य संगठनों में नियोजित हैं और अपने अपने ड्यूटी स्टेशनों पर पृथक् रूप में भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करते हुए भिन्न भिन्न चिकित्सा सुविधाओं का उपभोग कर रहे हैं, तब संबंधित कर्मचारी, यथास्थिति, अपनी बाबत तथा उसके साथ निवास करने वाले तथा इन विनियमों के अंतर्गत आने वाले कुटुंब सदस्यों की बाबत इन विनियमों के अधीन चिकित्सीय सुविधा का उपभोग कर सकता है:

परंतु -

(क) यदि पति या पत्नी को नियत चिकित्सा भत्ता प्राप्त होता है, तो कर्मचारी पति या पत्नी के सिवाय अपने तथा अपने साथ निवास कर रहे कुटुंब सदस्यों के लिए इन विनियमों के अधीन चिकित्सा प्रतिपूर्ति का उपभोग कर सकता है; और

(ख) वह अपने पति या पत्नी के नियोजक से एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता है कि वह अपने पति या पत्नी और उनके कुटुंब सदस्यों की बाबत चिकित्सीय सुविधा का दावा नहीं कर रहा है।

(5) महिला कर्मचारी को यह विकल्प होगा कि वह इन विनियमों के अधीन और समय समय पर जारी अनुदेशों के अधीन इन विनियमों में अनुबंधित रूप में आश्रितता और निवास की शर्तों के अधीन रहते हुए चिकित्सीय रियायतों के फायदों का उपभोग करने के प्रयोजन के लिए या तो अपने माता पिता या अपने सास ससुर को सम्मिलित करे।

स्पष्टीकरण-

(i) प्रत्येक महिला कर्मचारी को अपने विवाह के तुरंत पश्चात् एक घोषणा देनी चाहिए कि क्या वह इन विनियमों के अधीन चिकित्सा रियायतों के फायदे के प्रयोजन के लिए अपने माता पिता को सम्मिलित करना चाहेगी या सास ससुर को। वह संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान एक बार अपने विकल्प में परिवर्तन कर सकती है;

(ii) विवाह पर दोनों पति और पत्नी से, यदि कार्य कर रहे हैं, अपेक्षा की जाएगी कि वे अपने विकल्प की घोषणा दें जिसमें कुटुंब के प्रत्येक सदस्य की बाबत स्पष्टतः विस्तृत रूप में यह उपदर्शित किया जाए कि किनकी बाबत संबंधित पति या पत्नी द्वारा दावा किया जाएगा। घोषणा की एक प्रति कार्यालय द्वारा प्रत्येक पति या पत्नी की वैयक्तिक फाइल में रखी जाएगी।

(6) प्राधिकरण का कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति पर इन विनियमों के अधीन आश्रित के रूप में फायदा प्राप्त करने के लिए पात्र है यदि उसका पुत्र या पुत्री या पत्नी प्राधिकरण में नियोजित है परंतु यह तब जब वह सेवानिवृत्ति की तारीख से 2 (दो) मास की अवधि के भीतर तथा इन विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए इन विनियमों के अधीन चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने का विकल्प देता है। यद्यपि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा तथापि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए प्राधिकरण की चिकित्सा फायदे के लिए विकल्प के अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा।

4. औषधालयों की स्थापना - (1) प्राधिकरण अपने प्रत्येक विमानपत्तनों या यूनियों और अपने मुख्यालयों पर एक औषधालय या चिकित्सा निरीक्षण कक्ष की स्थापना करेगा और उपचार के प्रयोजन के लिए एक या अधिक चिकित्सा परिचर और अन्य कर्मचारिवृन्द की, जो आवश्यक समझे जाएं, पूर्णकालिक या अंशकालिक आधार पर नियुक्तियों का तथा उनमें विहित औषधियों का स्टॉक रखा जाएगा।

(2) औषधालय या चिकित्सा निरीक्षण कक्ष में परामर्श या उनसे कर्मचारियों और उनके कुटुंब के लिए औषधियों तथा औषधियों का प्रदाय निःशुल्क किया जाएगा।

5. परामर्श के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति- प्राधिकरण द्वारा स्थापित औषधालयों और चिकित्सा निरीक्षण कक्षों में चिकित्सा परिचरों की नियुक्ति के अतिरिक्त प्राधिकरण इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए किसी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी की प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति भी करेगा।

6. आयुर्विज्ञान की प्रणाली - कर्मचारी और उनके कुटुंब के सदस्य निम्नलिखित आयुर्विज्ञान की किसी प्रणाली के अधीन उपचार ले सकेंगे:-

(i) आयुर्विज्ञान की एलोपैथी प्रणाली;

(ii) आयुर्विज्ञान की होम्योपैथी प्रणाली ;

(iii) आयुर्विज्ञान की आयुर्वेद प्रणाली ; और

(iv) आयुर्विज्ञान की यूनानी प्रणाली ।

7. औषध- जब चिकित्सा परिचर या चिकित्सा व्यवसायी या प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा औषधियों का नुस्खा लिखा जाता है उनकी तभी प्रतिपूर्ति की जाएगी जब औषधियां अनुज्ञेय औषधियों की सरकारी सूची के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

8. चिकित्सा उपचार के लिए प्रक्रिया- (1) कर्मचारी द्वारा या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा सामान्यतया चिकित्सा उपचार, पैनल में रखे गए निकटत नर्सिंग होम या अस्पतालों में सीमा या हकदारी के अनुसार तथा समय समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों के अनुसार लिया जाएगा ।

(2) कोई कर्मचारी स्वयं के या अपने कुटुंब के सदस्यों का उपचार कराने के लिए पैनल पर रखे और चुने हुए नर्सिंग होम या अस्पतालों में विस्तारित की गई उधार सुविधा का उपभोग कर सकेगा ।

(3) कोई कर्मचारी अपना और अपने कुटुंब का उपचार कराने के लिए पैनल पर रखे गए अस्पताल के संस्थागत अस्पतालों के प्राइवेट बाह्य रोगी विभाग में बैठे चिकित्सक या विशेषज्ञ का परामर्श ले सकेगा ।

(4) प्राधिकरण परामर्श फीस या निरीक्षण फीस और अस्पताल या नर्सिंग होम के प्रभार नियत करेगी जिसकी कर्मचारी को प्रतिपूर्ति की जा सकेगी ।

9. चिकित्सा व्यय की चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया-

(1) चिकित्सा व्यय के सभी संदाय प्रथम बार कर्मचारी द्वारा किए जाएंगे । तत्पश्चात् चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा इन विनियमों से उपाबद्ध प्ररूप में प्रस्तुत किया जाएगा जो सम्यक् रूप से नुस्खा, बिल, नकद रसीदों और कौश मैमो या ऐसे कोई अन्य सुसंगत दस्तावेज, जो समय समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, समर्थित होगा ।

(2) चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए दावा उपचार पूरा होने के दिन से तीन मास के भीतर सक्षम प्राधिकारी को किया जाना चाहिए । कालातीत दावा उपचार पूरा होने के दिन से तीन मास

की अवधि के उपरांत किंतु एक वर्ष के भीतर ग्रहण किया जा सकता है यदि सक्षम प्राधिकारी का प्रत्येक मामले में यह समाधान हो जाता है कि दावा प्रस्तुत करने में हुआ विलंब कर्मचारी के नियंत्रण से परे के कारण से हुआ है।

(3) प्राधिकरण किसी कर्मचारी या उसके कुटुंब के सदस्य द्वारा उसके मुख्यालय से किसी भिन्न स्थान पर प्राप्त किए गए चिकित्सा परिचर्या और/या उपचार की बाबत उसके दावा के समर्थन में संतोषप्रद दस्तावेजी सबूत के आधार पर प्रतिपूर्ति करके परंतु यह तब जबकि उपचार केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार/नगर निगम/नगर समिति के नियंत्रण के अधीन किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या अस्पताल से और पैनल पर के नर्सिंग होम, जो प्राधिकरण द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए, से कराया गया है।

(4) सक्षम प्राधिकारी अपने एकमात्र विवेकाधिकार से प्रतिपूर्ति के दावे को नामंजूर कर सकेगा यदि कर्मचारी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत से उसका समाधान नहीं होता है।

10. कर्मचारियों या उनके कुटुंब की बाबत कतिपय परिस्थितियों में चिकित्सा उपचार - ऐसे कर्मचारियों की बाबत जिन्हें प्रशिक्षण/ लघुकाल के समनुदेशन पर विदेश भेजा गया है, कर्मचारियों की प्रास्थिति के अनुसार चिकित्सा सुविधाएं भारतीय रिज़र्व बैंक या सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा के लिए समाशोधन के अधीन रहते हुए उपलब्ध कराई जाएगी।

11. निम्नलिखित मामलों में कोई प्रतिपूर्ति अनुज्ञेय नहीं होगी,—

(i) खुराक प्रभार ;

(ii) प्रवहन प्रभार ; और

(iii) अस्पताल में परिचर की बाबत उपगत प्रभार ।

12. बाह्य रोगी उपचार - (1) कर्मचारी एलोपैथिक, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक और यूनानी उपचार के लिए अपनी पसंद के प्राइवेट रजिस्ट्रीकृत व्यवसायी से उपचार करा सकेगा और चिकित्सकों द्वारा प्रभारित वास्तविक फीस की प्रतिपूर्ति समय समय पर नियत सीमा के अधीन रहते हुए तथा एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी के एक मास के मूल वेतन धन महंगाई भत्ता (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार) के निर्बंधन के अधीन रहते हुए भी की जाएगी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

वाह्य रोगी उपचार के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी या रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी का पैनल भी बना सकेगा और निर्बंधन लगा सकेगा।

(2) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक मास का मूल वेतन धन महंगाई भत्ता का निर्बंधन चिकित्सा उपचार के नेमी प्रकार के संदर्भ में है। तथापि विशेष जीवन को संकटमय बनाने वाली ऐसी बीमारियों के लिए जो समय समय पर विनिश्चित की जाए चिकित्सा की लागत पर बाह्य रोगी उपचार के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में (1 अप्रैल की स्थिति के अनुसार) एक मास के मूल वेतन धन महंगाई भत्ता की अधिकतम सीमा को संगणना करते समय विचार में नहीं लिया जाएगा और उन पर जब अपेक्षित हो, निर्बंधन लगाया जा सकेगा।

(3) रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी / प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के लिए न्यूनतम अर्हताएं एलोपैथी के लिए बैचलर आफ मेडिसिन एंड बैचलर आफ सर्जरी (एमबीबीएस) और बैचलर आफ डेंटल सर्जरी, होम्योपैथी के लिए बैचलर आफ होम्योपैथिक मेडिकल साइंसेज, आयुर्वेदिक के लिए बैचलर आफ आयुर्वेदिक मेडिकल साइंसेज तथा आयुर्विज्ञान की यूनानी प्रणाली के लिए बैचलर आफ यूनानी मेडिकल साइंसेज है तथा विशेषज्ञ के लिए डाक्टर आफ मेडिसिन या मेडिकल सर्जन या उसके ऊपर है।

(4) जहां रोगी की दशा से ऐसा अपेक्षित हो, रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी / प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी क्लिनिक में उपचार के लिए निकटतम प्राइवेट विशेषज्ञ के पास भेज सकता है।

13. अंतरंग उपचार - (1) अस्पताल में दाखिल करने के मामले में रोगी को अस्पताल या नर्सिंग होम में दाखिल किया जा सकता है।

(2) कर्मचारी या उसके आश्रित के लिए सरकारी या प्राधिकरण के पैनल में से प्राइवेट, संस्थागत अस्पताल, नर्सिंग होम में अंतरंग उपचार के लिए लागू कक्ष किराया प्रभार की हकदारी वह होगी जो समय समय पर नियत की जाए।

14. आपात्कालिक मामलों में गैर अधिसूचित अस्पताल में उपचार-

(1) कोई कर्मचारी या उसके कुटुंब का सदस्य आपात्कालिक उपचार के लिए गैर अधिसूचित अस्पताल से निकट किसी अधिसूचित अस्पताल या नर्सिंग होम के अभाव में, निकटतम और अधिसूचित अस्पताल में (जिसके अंतर्गत प्राइवेट नर्सिंग होम / प्राइवेट क्लिनिक है) दाखिल

किया जा सकता है । इस प्रश्न पर कि क्या यह मामला गैर अधिसूचित अस्पताल / नर्सिंग होम में वास्तविक आपात्काल में दाखिल करने हेतु आवश्यक था, सक्षम प्राधिकारी द्वारा गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा ।

(2) यदि कर्मचारी द्वारा गैर अधिसूचित अस्पताल में उपचार कराया जाता है, तो उसकी हकदारी तक सीमित वास्तविक आवास प्रभार तथा प्राधिकरण द्वारा समय समय पर नियत रूप में प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

15. विनिर्दिष्ट बीमारियों के लिए उपचार या साधन और उपस्करों आदि के लिए प्रभार - उपचार और विभिन्न उपस्करों और साधन के लिए व्ययों / प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया संबंधी अनुदेश समय समय पर अपेक्षानुसार पृथक् रूप से जारी किए जाएंगे ।

16. यात्रा भत्ता - कर्मचारी और उनके कुटुंब के सदस्य, जब उन्हें चिकित्सा अधिकारी द्वारा उस स्टेशन से जहां कर्मचारी तैनात है, बाहर किंतु जिले के भीतर चिकित्सा उपचार या परिचर्या के लिए किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ या अस्पताल के लिए निदेशित किया जाता है, प्राधिकरण के यात्रा भत्ता विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ता के संदाय के हकदार होंगे । एक परिचर या मार्गक्षी के लिए यात्रा भत्ता भी अनुज्ञात किया जाएगा यदि चिकित्सा अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि रोगी के लिए बिना परिचर के यात्रा करना असुरक्षित है । जिला के बाहर के चिकित्सा अधिकारी या विशेषज्ञ द्वारा या अस्पताल में उपचार कराने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी अभिप्राप्त की जानी चाहिए । इसमें असफल होने पर यात्रा भत्ता व्यय और चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

17. चिकित्सा परिचर्या और उपचार तथा क्रेडिट सुविधा के लिए अग्रिम की मंजूरी-

(1) कर्मचारियों को अपने और अपने कुटुम्ब के सदस्यों के लिए प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी की सिफारिश के आधार पर चिकित्सा व्यय को चुकाने के लिए, यदि अपेक्षित हो, समय-समय पर सीमा और शर्तों के अनुसार चिकित्सा अग्रिम प्रदान किया जा सकता है ।

(2) चिकित्सा अग्रिम निम्नलिखित प्रयोजन के लिए अनुज्ञेय है, अर्थात् :-

(i) अस्पताल/नर्सिंग होम में अंतरंग रोगी के उपचार के लिए ;

(ii) यक्ष्मा/कैंसर/चिरकालिक रोग के मामले में बाह्य रोगी के रूप में ; और

- (iii) अनुज्ञेय कृत्रिम उपस्कर के क्रय, प्रतिस्थापन, मरम्मत और ठीक कराने के लिए ।
- (3) चिकित्सा अग्रिम निम्नलिखित दशाओं में प्रदान किया जा सकता है, अर्थात् :—
- (i) उपचार की अवधि और प्रत्याशित लागत चिकित्सा अधिकारी/विशेषज्ञ द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए ;
 - (ii) एक ही बीमारी/क्षति के लिए समय-समय पर विहित सीमा के अध्यक्षीन अग्रिम एक या अधिक किस्तों में संदत्त किया जा सकता है ;
 - (iii) संदेय अग्रिमों की संख्या के प्रति कोई सीमा नहीं है ;
 - (iv) गंभीर बीमारी/दुर्घटना की दशा में, जहां कर्मचारी अग्रिम के लिए आवेदन करने में असमर्थ है वहां अग्रिम कर्मचारी की पत्नी या कुटुम्ब के सदस्य के आवेदन पर मंजूर किया जा सकता है ;
 - (v) यथास्थिति, अस्पताल या नर्सिंग होम के चिकित्सक या चिकित्सा अधिकारी से प्राक्कलन की प्राप्ति पर अग्रिम सीधे अस्पताल या नर्सिंग होम को भेजा जा सकता है ; और
 - (vi) कृत्रिम उपस्कर के मामले में, संदाय सीधे प्रदाय करने वाले अभिकरण या अस्पताल को किया जाएगा जो ऐसे उपस्कर का प्रदाय करता है ।
- (4) चिकित्सा अग्रिम का समायोजन निम्नलिखित रूप में किया जाएगा, अर्थात् :—
- (i) अग्रिम का समायोजन चिकित्सा दावा से किया जाएगा और अतिशेष, यदि कोई हो, सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर वेतन में से एक या अधिक किस्तों में किया जाएगा ;
 - (ii) लंबे उपचार में, प्रतिपूर्ति संबंधित चिकित्सा अधिकारी द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र दिए जाने तक जारी रह सकती है कि अब रोगी को उपचार की आवश्यकता नहीं है और अग्रिम का समायोजन अंतिम दावा में से किया जा सकता है ;

- (iii) यदि अग्रिम सीधे अस्पताल को संदत्त किया जाता है तो कर्मचारी द्वारा अंतिम समायोजन अस्पताल से छुट्टी मिलने के एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाना चाहिए । वित्त और लेखा विभाग अस्पताल से अप्रयुक्त अग्रिम, यदि कोई हो, के बारे में पत्राचार करेगा ;
- (iv) यदि चिकित्सा दावा के समायोजन के मामले में कोई उपेक्षा या चूक पायी जाती है तो व्यक्तिक्रमी वाले मामलों में अनुशासनिक कार्रवाई के अतिरिक्त शास्तिक ब्याज अधिशेषित किया जाएगा ।

18. सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधा स्कीम :- कर्मचारी अधिवर्षिता पर उनकी सेवानिवृत्ति के पश्चात् स्कीम के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अंशदायी आधार पर अपने और अपने पति या पत्नी के चिकित्सा फायदे के लिए हकदार होंगे (यद्यपि एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अंतिम होगा तथापि इन विनियमों के अधीन चिकित्सा फायदा के विकल्प के बारे में अनुरोध पर प्रत्येक मामले में गुणागुण के आधार पर विनिश्चय किया जाएगा यदि सेवानिवृत्त कर्मचारी का पुत्र या पुत्री या पति या पत्नी प्राधिकरण में कार्य कर रहा है/रही है और अन्य अधिकथित शर्तों को पूरा करने की इच्छुक है)।

19. चिकित्सा सुविधा आदि के लिए अन्य शर्तें-- किसी कर्मचारी की चिकित्सा सुविधा की ऐसे विषयों के बारे में शर्तें जिनके लिए इन विनियमों में कोई उपबंध नहीं है, वही होंगी जो भारत सरकार के तत्समान प्रास्थिति के अन्य कर्मचारियों को तत्समय लागू हो ।

20. शिथिल करने की शक्ति-- जब अध्यक्ष की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा ऐसे कारणों के आधार पर जो लेखबद्ध किए जाएंगे, कर्मचारियों के किसी वर्ग या प्रवर्ग की बाबत इन विनियमों के किसी उपबंध को शिथिल कर सकेगा ।

टिप्पण : दीर्घकालिक रोग के मामले में कृपया साधारण अनुभाग द्वारा जारी पत्र की फोटो प्रति संलग्न करें ।

कृपया एक ही स्तंभ में एक से अधिक संदाय को सम्मिलित न करें ।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि :

1. उमर दी गई विशिष्टियाँ सही हैं ।
2. वे व्यक्ति जिनकी बाबत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, मेरे उमर पूर्णतया आश्रित हैं और वे मेरे साथ निवास कर रहे हैं । वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम या किसी अन्य चिकित्सा स्कीम के अधीन नहीं आते हैं ।
3. उन टीका प्रमारों का जिनका अब दावा किया जा रहा है, उनका पहले दावा नहीं किया गया है ।
4. मैं.....से.....की अपनी बीमारी के दौरान छुट्टी पर था जिसके लिए बिल में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है ।
- 5.

तारीख :

इंटरकाम

(दावा करने वाले के हस्ताक्षर)

कार्यालय प्रयोग के लिए		
यह दावा निम्नलिखित संप्रदायों के साथ वापस किया जाता है :		
1. नुस्खे में लिखी गई ओषधि का क्रय नहीं किया गया है ।	डाक्टर	सहायक एएएम(सी)
2. दावा अपूर्ण है ।		
सहायक एएएम(सी)		

2. वे व्यक्ति जिनकी बाबत चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है, मेरे ऊपर पूर्णतया आश्रित हैं और वे मेरे साथ निवास कर रहे हैं। वे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा स्कीम या किसी अन्य चिकित्सा स्कीम के अधीन नहीं आते हैं।
3. मैं.....से.....की अपनी बीमारी के दौरान छुट्टी पर था जिसके लिए बिल में चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा किया गया है।

तारीख : इंटर्काम

कार्यालय प्रयोग के लिए			
यह दावा निम्नलिखित संश्लेषणों के साथ वापस किया जाता है :			
1. नुरखे में लिखी गई ओषधि का क्रय नहीं किया गया है।	रुपए (.....रुपए) के संदाय के लिए पास किया गया।	
2. दावा अपूर्ण है।			
सहायक	एएम(सी)	डाक्टर	सहायक एएम(सी)

एस. के. नरुला, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/IV/158/2002/असा०]

MINISTRY OF CIVIL AVIATION
(AIRPORTS AUTHORITY OF INDIA)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th June, 2003

F. No. AAI/Pers/EDPA/Reg./2002.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1), read with clause (b) of Sub-section (2) of Section 42 of the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994) and in supersession of the International Airports Authority of India (Medical Attendance and Treatment) Regulations, 1976 and the National Airports Authority (Medical Attendance) Regulations, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Airports Authority of India, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title, commencement and application. — (1) These Regulations may be called the Airports Authority of India (Employees Medical Attendance and Treatment) Regulations, 2003.

- (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette
- (3) They shall apply to all the employees of the Authority, except;
 - (a) Persons in casual or daily rated or part-time employment;
 - (b) Persons on deputation to the Authority, unless their terms of deputation provides otherwise;
 - (c) Persons employed on contract unless the terms of contract provide otherwise;
 - (d) Apprentices or trainees on a stipend.

2. Definitions.— (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the Airports Authority of India Act, 1994 (55 of 1994);
- (b) "Authority" means the Airports Authority of India/ constituted under Section 3 of the Act;
- (c) "Authorized Medical Officer" means a Medical Officer who is appointed by the Authority either in full time, part-time or retainer-ship basis or any registered medical practitioner possessing minimum qualification as Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery /Bachelor of Dental Surgery / Bachelor of Ayurvedic Medicine System / Bachelor of Unani Medicine System;
- (d) "Chairperson" means the Chairperson of the Authority appointed under Clause (a) of sub-section (3) of Section 3 of the Act;
- (e) "City" means the headquarters city or town of the employee;
- (f) "Competent Authority" means the Chairperson or a whole-time Member or any other Officer authorized by the Chairperson in this behalf;
- (g) "Dispensary" means a dispensary established by the Authority under these regulations;
- (h) "Employee" means a whole time employee of the Authority;

- (i) "Family" means a employee's wife or husband, as the case may be, and parents (not step parents), children and step children, adopted children (if adoption is permissible under Personal law), sister, widowed sister, widowed daughter, minor brothers, wholly dependent on the employee as per the laid down conditions for dependency;
- (j) "Hospital" means a dispensary or Medical Inspection Room established or run by the Authority or maternity centre administered by the Central Government or State Government or a local authority or Public Sector Undertaking, Military Hospital, Railway Hospital, All India Institute of Medical Science (AIIMS), any Medical Institute or College or Research Centre established or run or recognised by the Central Government or State Government or University established by University Grants Commission or Medical Council of India ; or any hospital notified by the Authority from time to time;
- (k) "Medical Attendance" means attendance by an Authorised Medical Officer or any other registered Medical Practitioner possessing minimum qualification as Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery /Bachelor of Dental Surgery / Bachelor of Ayurvedic Medicine System / Bachelor of Unani Medicine System in a hospital or Nursing Home or at clinic or at the residence of the employee and includes any examination for the purpose of diagnosis and/or treatment as may be considered necessary by the said Medical Officer or Practitioner;
- (l) "Member" means the member of the Authority other than ex-officio member;
- (m) "Nursing Home" mean Nursing Homes on the panel of the Authority;
- (n) "Pay" means basic pay, special pay or other emoluments classified as pay drawn by the employee at the time of treatment;
- (o) "Treatment" means the use of medical and/or surgical facilities as are considered necessary by the Authorized Medial Attendant and includes,-

- (i) the employment of pathological, bacteriological, radiological and other methods;
- (ii) the supply of medicines, vaccines, sera or other therapeutic substances;
- (iii) ordinary dental treatment except supply of dentures, crown work, bridge work, orthodontic work and other specialized dental work;
- (iv) treatment of eyes and testing of eye sight except supply of spectacles;
- (v) prenatal, confinement and post-natal treatment;
- (vi) insulin treatment in the case of patients suffering from diabetes recommended by concerned specialist and whenever required;
- (vii) anti-rabbi treatment;
- (viii) ordinary nursing and hospital accommodation appropriate to the status of the employee; and
- (ix) special tests or investigations referred by concerned specialist.

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act or any rule or regulations made there under, shall have the same meaning respectively as assigned to them in that Act or rules or regulations made thereunder.

3. Conditions for dependency. - (1) A member of the family whose total income from all sources, including pension, temporary increase on pension or stipend, etc. does not exceed Rs.1500/- per month is deemed to be wholly dependant on the employee. However, husband and wife shall be considered as one unit for the purpose of these regulations and dependency limit shall not be applicable to wife or husband.

Note : (i) The Competent Authority may alter the dependency limit or conditions of dependency delete or add or alter any additional condition for the members of the family (including spouse) under these regulations;

- (ii) Each employee shall furnish a declaration every year about the status and dependency of his parents and other family members at the beginning of the year to allow them to avail the medical facilities under these regulations.

Explanation. – (i) The residential condition for members of families is not essential. Family members may have medical attendance and treatment if they do not stay with the employee. Parents can live away from the employee at another station with other members of the family, provided the employee has not claimed Travelling allowance or Daily Allowance at the time of transfer for parents and family;

(ii) Recurring income from sources such as business, employment, property, agriculture, houses land holding, etc, shall be taken into account for the purpose of assessing income;

(iii) Lump-sum non-recurring income, such as, Contributory Provident Fund Benefits, Government of India Price Bonds, Gratuity, Commuted Gratuity, Insurance Benefits, etc. shall not be regarded as a part of income.

(2) In case where both husband and wife are employed in the Authority, they, as well as their eligible dependants may be allowed to avail of the medical concessions according to his or her status. For this purpose, a joint declaration as to who shall prefer the claim for reimbursement of medical expenses incurred or the medical attendance and treatment irrespective of wife or husband and the children shall be furnished. If declaration is not furnished, concession is to be availed by all including wife according to the status of the husband. The option given in the declaration can be changed from the next financial year as and when necessary depending on change in circumstances.

(3) Employee's spouse employed in Central Government, State Government, Public Sector Undertakings, Local Bodies or Private Organisations, as the case may be, which provides medical facilities, is allowed to choose either the facilities under these regulations or, the medical facilities provided by the organisation in which he or she is employed on the basis of a certificate from the employer of his or her spouse that he or she is not claiming medical facilities in respect of his or her spouse and their family members. For this purpose they should furnish to their authorities a joint declaration in duplicate as to who shall prefer the claim for reimbursement of medical expenses in respect of wife or husband and dependent family members with full details in respect of them. A copy each of the joint declaration, in duplicate, shall be recorded in the personal file of each of them in their respective organisation. The option given in the declaration can be changed or altered from the next financial year as and when necessary.

(4) When the employee and whose spouses are employed in other organisations availing different medical facilities and stationed and residing at different places separately at their respective duty stations, the employee concerned may avail medical facilities, under these regulations in respect of himself or herself, as the case may be, and the family members residing with him or her and covered under these regulations:

Provided that, -

- (a) if the spouse is in receipt of fixed medical allowance, the employee may avail medical reimbursement under these regulations for himself or herself and members of family residing with his or her except the spouse; and
- (b) he or she produces a certificate from the employer of his or her spouse that he or she is not claiming medical facilities in respect of his or her spouse and their family members.

(5) A female employee shall be given the choice to include either her parents, or her parents-in-law for the purpose of availing of the benefits of the medical concessions under these regulations and instructions issued from time to time, subject to the conditions of dependency and residence as stipulated in these regulations.

Explanation.-

- (i) Every female employee should immediately after her marriage give a declaration as to whether she shall like to include her parents or parents-in-law for the purpose of benefits of medical concessions under these regulations. She can change her option only once during the entire period of her service;
- (ii) Both husband and wife on marriage, if working, shall be required to give a declaration of their option, clearly indicating the details in respect of each member of family in respect of whom the claim is to be preferred by the spouse concerned. A copy of the declaration may be retained in personal file by the office of each spouse.

(6) An employee of the Authority on retirement is eligible to avail the benefit under these regulations as dependent if his or her son or daughter or wife is employed in the Authority provided he gives an option to avail medical facilities under these regulations within a period of 2 (two) months from the date of retirement, and subject to meeting the other conditions as specified in these regulations. Though the option once exercised shall be final, however, the request to opt for Authority medical benefits for retired employees will be decided on merit of each case.

4. Establishment of dispensaries. – (1) The Authority may establish a dispensary or Medical Inspection Room at each of its airports or units and at its Headquarters and appoint one or more medical attendants and other staff as may be considered necessary for the purpose of treatment on the whole time or part time basis and prescribe medicines to be stocked therein.

(2) Consultation at the dispensary or Medical Inspection Room or supply of medicines and drugs there from shall be free of charge to the employees and their families.

5. Appointment of authorised medical officer for consultation. - In addition to the appointment of Medical Attendants at the dispensaries or Medical Inspection Room established by the Authority, the Authority may also appoint any registered Medical Practitioner as Authorized Medical Officer for the purposes of these regulations.

6. System of medicines.- The employees and their family members may get treatment under any of the under mentioned systems of medicines:-

- (i) Allopathy system of medicine;
- (ii) Homeopathy system of medicine;
- (iii) Ayurvedic system of medicine; and
- (iv) Unani system of medicine.

7. Medicines.- When medicines are prescribed by the Medical Attendant or Medical Practitioner or Authorised Medical Officer, the same will be reimbursed only if the medicines are admissible under the Government list of admissible medicines.

8. Procedure for medical treatment.- (1) Medical treatment shall normally be taken by the employee or a member of his or her family at the nearest empanelled Nursing Homes or Hospitals as per the limits or entitlements and other conditions as specified by the Authority from time to time.

(2) An employee may avail the credit facility extended to the selected empanelled Nursing Homes or Hospitals for getting treatment of self and his or her family members.

(3) An employee may avail the consultation of the doctor or specialists sitting in the Private Out Patient Department of the Institutional Hospitals of the empanelled hospital for getting treatment of self and his or her family members.

(4) The Authority shall fix the limits of consultation fee or visiting fee and Hospital or empanelled Nursing Home charges which may be reimbursable to the employee.

9. Procedure for medical reimbursement of medical expenses.- (1) All payments of medical expenses shall be made by the employee in the first instance. Claims for reimbursement of medical expenses shall subsequently be submitted in the Form annexed to these regulations duly supported by the prescription, bills, cash receipts and cash memos or any other relevant documents as may be specified by the Competent Authority from time to time.

(2) The claims for reimbursement of medical expenses should be submitted to the Competent Authority within three months from the day of completion of the treatment. The time barred claims may be admitted beyond three months but within one year from the date of completion of treatment if the Competent Authority is satisfied in each case that the delay in submission of claims is for reasons beyond the control of employee.

(3) The Authority may reimburse charges in respect of medical attendance and / or treatment received by an employee or his family at a place other than his headquarters on the basis of satisfactory documentary proof in support of his claim provided that the treatment is taken from an Authorised Medical Officer or Hospital under the control of the Central Government/ State Government / Municipal Corporation / Municipal Committee and empanelled Nursing Homes as specified by the Authority from time to time.

(4) The Competent Authority may at its sole discretion disallow claim for reimbursement if it is not satisfied with the documentary proof produced by an employee in support of his or her claim.

10. Medical treatment in respect of employees or their families in circumstances. – In respect of employees sent abroad for training / short terms assignments, medical facilities appropriate to the status of the employees shall be provided subject to the clearances by the Reserve Bank of India or Government for foreign exchange.

11. No reimbursement shall be admissible in the following cases,-

- (i) Diet Charges
- (ii) Conveyance Charges, and
- (iii) Charges incurred in respect of an attendant at the hospital.

12. Out patient treatment - (1) Employees may receive medical attendance and treatment from private registered practitioners of their choice for Allopathic, Homeopathy, Ayurvedic and Unani treatment and actual fees charged by the Doctors shall be reimbursed subject to the limit fixed from time to time and also restrictions in each financial year to one month Basic Pay Plus Dearness Allowance (as on 1st April) of the employee. AAI may also empanel Authorized Medical Officer or Registered Medical Practitioners for out patient treatment and put restrictions.)

(2) The restriction of one month's basic pay plus Dearness Allowance in each financial year is with reference to routine type of medical treatment. However, the cost of the medicines for special / life threatening diseases as decided from time to time shall not be considered while computing the ceiling of one month's Basic Pay plus Dearness Allowance (as on 1st April) in each financial year for out patient treatment and also can put restriction as and when required.

3) Minimum qualifications for Registered Medical Practitioners / Authorised Medical Officer will be Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) and Bachelor of Dental Surgery for Allopathy, Bachelor of Homeopathic Medical Sciences for Homeopathy, Bachelor of Ayurvedic Medical Sciences for Ayurvedic and Bachelor of Unani Medical Sciences for Unani system of medicines and for Specialists shall be Doctor of Medicine or Medical Surgeon or above.

4) Where the condition of the patient so requires Registered Medical Practitioner / Authorized Medical Attendant can refer to nearest private specialist for treatment at the clinic.

13. Indoor Treatment- (1) In cases of Hospitalization, the patient may be admitted to the Hospitals or Nursing Homes.

(2) The entitlement of room rent charges applicable for indoor treatment for the employees and their dependents in Government or Private, Institutional Hospitals, Nursing Homes empanelled by the Authority shall be as fixed from time to time.

14. Treatment in a non-notified hospital in emergent cases. - (1) An employee or a member of his or her family may be admitted for emergent treatment in the nearest non-notified hospital (including private Nursing Home / Private Clinic) in the absence of a notified hospital or Nursing Home nearer than the non-notified hospital. The question whether it was a case of real emergency necessitating admission in such non-notified hospital Nursing Homes will be decided on merits of each case by the Competent Authority.

(2) If treatment is taken in a non-notified hospital by the employees reimbursement of actual accommodation charges limited to the entitlement and prescribed rates as fixed by the Authority from time to time shall be made.

15. Treatment for specified diseases or charges for aid and appliances etc. - Instructions regarding Procedure for treatment and reimbursement of expenses / charges for various Appliances or Aid shall be issued separately as per requirements from time to time.

16. Travelling Allowance. - Employees and their family members shall be entitled to payment of travelling allowance in terms of Travelling Allowance Regulations of the Authority when directed by the Medical Officer for medical attendance or treatment to another Medical Officer or Specialist or hospital outside the station at which the employee is posted but within the District. Travelling Allowance for one attendant or escort shall also be allowed if it is certified by the Medical Officer that it is unsafe for the patient to travel unattended. In case of

reference made to Medical Officer or Specialist or Hospital outside the District, prior sanction of the Competent Authority should be obtained for taking medical treatment outside the place of his posting. Failing this, the Travelling Allowance expenses and claims of reimbursement of medical expenses shall not be accepted.

17. Grant of advance for medical attendance and treatment and credit facilities.—

(1) The medical advance may be granted, if required, to the employees to meet the expenditure on medical attendance and treatment for themselves and the members of their families on the basis of recommendation of the Authorised Medical Officer as per the limit and conditions from time to time.

(2) The Medical advance is admissible for the following purpose, namely:-

- (i) for in-patient treatment in a hospital / Nursing Home
- (ii) as an out-patient in the cases of TB/Cancer / Chronic diseases; and
- (iii) purchase, replacement, repair and adjustment of admissible artificial appliances.

(3) The Medical Advance may be granted on the following conditions, namely:-

- (i) The duration and anticipated cost of treatment should be certified by the Medical Officer / Specialists;
- (ii) Advance can be paid in one or more installments for the same illness / injury subject to the limit prescribed from time to time;
- (iii) There is no limit with reference to number of advances payable;
- (iv) In case of serious illness / accident where the employee is unable to apply for advance, the advance may be sanctioned on the application of wife or family members of the employee;
- (v) The advance shall be paid directly to the Hospital or Nursing Home concerned on receipt of an estimate from the Physician or Medical Officer of Hospital or Nursing Home, as the case may be; and
- (vi) In the case of artificial appliances, the payment shall be made directly to the supplying agency or Hospital which should supply such appliances.

(4) The medical advance shall be adjusted in the following manner, namely:-

- (i) the advance shall be adjusted against the medical claim and the balance, if any, from pay in one or more installments at the discretion of the Competent Authority;
- (ii) in prolonged treatment, reimbursement may continue till the concerned medical officer gives the certificate that the patient no more requires treatment and advance may be adjusted in final claim.
- (iii) if advance is paid directly to Hospital, the final settlement should be submitted by the employee within one month of discharge from hospital. Department of Finance and Accounts shall correspond with the hospital for refund of unutilized advance, if any.
- (iv) in case, any negligence or default is found in case of adjustment of medical claim, penal interest shall be imposed in defaulting cases besides disciplinary action.

18. Medical benefit scheme for retired employees.— The employees shall be entitled for medical benefits for themselves and their spouse subsequent to their retirement on superannuation on contributory basis as per the terms and conditions of the Scheme. (Though the option once exercised shall be final, however the request to opt the medical benefits under these Regulations) shall be decided on merit of each case if the son or daughter or spouse of the

retired employee is working in the Authority and is willing subject to meeting the other laid down conditions).

19. Other conditions of medical facilities etc. - The conditions of medical facilities of an employee in respect of matters for which no provision is made under these regulations shall be the same as may for the time being be applicable to other employees of the Government of India of a corresponding status.

20. Power to relax.- When the Chairperson is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of employees.

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रतिलिपि सही है।
[Signature]

(Signature of Claimant)

